आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर
दिनांक : 24.07.2024
समय : 0705
<><><><><><><><>

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया।
- बजट में दो लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से पांच वर्ष की अवधि में चार करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढ़ाने की पांच योजनाओं और पहल के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा।
- करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती पचास हजार रुपये से बढ़ाकर पचहत्तर हजार रुपये की गई।
- वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए दो लाख छियासठ हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की।
- सांसद बिष्णु पद रे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की।

<><><><><><><>

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने कल लोकसभा में वर्ष दो हजार चौबीस–पच्चीस का आम बजट पेश किया। यह नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। श्रीमती सीतारामण ने सातवीं बार बजट पेश किया है। वित्तमंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए दो घोषणाएं कीं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को पचास हजार रुपए से बढ़ाकर पचहत्तर हजार रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को पन्द्रह हजार रुपए से बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। तीन लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। तीन से सात लाख रुपए तक की आय पर पांच प्रतिशत, सात से दस लाख रुपए तक दस प्रतिशत, दस से बारह लाख रुपए तक पंद्रह प्रतिशत, बारह से पंद्रह लाख रुपए तक बीस प्रतिशत और पन्द्रह लाख रुपए से अधिक आय पर तीस प्रतिशत तक कर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में

वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में सत्रह हजार पांच सौ रुपए तक की बचत हो सकेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास कराधान को सरल बनाने का है।

हमने पिछले पाँच वर्षों में अनेक उपाय किए हैं जिसमें कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूट और कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं प्रारम्भ करना शामिल है। वित्तवर्ष दो हजार बाईस–तेईस में अट्ठावन प्रतिशत कॉरपोरेट कर सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा हुआ। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एम एस एम ई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू की जाएंगी। रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता के लिए सब्सिडी के रूप में एक महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरी योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरी योजना नियोक्ताओं पर केन्द्रित होगी। वित्तमंत्री ने बताया कि कृषि और सबंधित क्षेत्रों के लिए एक लाख बावन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए दो लाख छियासठ हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की है।

अगले दो वर्ष में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण–पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल है। दस हजार आवश्यकता आधारित संसाधन केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा है कि सरकार, जनजातीय समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि महिला नीत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार एक करोड़ शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए दस लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट विकसित भारत के लिए है जो चहुमुखी विकास सुनिश्चित करता है। ये समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन

योजनाओं से करोडो युवाओं को फायदा होगा। श्री मोदी ने कहा कि बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है।

<><><><><><><><>

सांसद बिष्णु पद रे ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद ने द्वीपसमूह से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।

<><><><><><><><>

सर्वोच्च न्यायालय ने नीट–यूजी दो हजार चौबीस की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से इन्कार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पूरी परीक्षा में गडबडी हुई, यह साबित करने का कोई प्रमाण नही मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। श्री प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार पारदर्शी और त्रुटिहीन परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है।

<><><><><><><><>

शैक्षिणिक सत्र दो हजार चौबीस–पच्चीस के लिए डॉ. बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, डॉलीगंज और डिगलीपुर के पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों की वरीयता सूची सामान्य कॉलेज प्रवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। सूची तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में भी दर्शा दी गई है। चयनित उम्मीदवारों से कल तक अपने शुल्क जमा करने को कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए कार्य दिवसों में सुबह नौ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक दिए गए नम्बर पर संपर्क कर सकते है।

<><><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान ज़िले के वन स्टॉप केन्द्र में केन्द्र प्रशासक, वकील, बहुद्देशीय कर्मी जैसे पदों में अनुबंध के आधार पर भर्ती की जाएगी। प्रशासन की वेबसाइट पर दिए गए सर्फेस मेल के जरिए या सीधे भी आवेदन किया जा सकता है। इक्कतीस जुलाई की शाम पांच बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

<><><><><><><><>

रंगत शैक्षिक अंचल के तहत चौदह वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़कों, सत्रह वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़कियों और उन्नीस वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़कों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट

आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल अडसठ टीमों ने भाग लिया। विभिन्न आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए कल सेमी फाइनल मैच खेला गया। आज फाइनल मैच खेला जाएगा।

<><><><><><><>

पोर्ट ब्लेयर में इस महीने की उनतीस तारीख से लेकर अगले महीने की बारह तारीख तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिजीत बैनर्जी और न्यायमूर्ति सुगातो मजूमदार मामलों की सुनवाई करेंगे।

<><><><><><><>

समाचार पत्रों की सुर्खियां

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री द्वारा संसद में केन्द्रीय बजट दो हजार चौबीस–पच्चीस पेश होने के समाचार को आज के अधिकांश समाचार पत्रो ंने अपनी बड़ी खबर बनाया है। मुख्य सचिव द्वार कुपोषण मुक्त पंचायत का वर्चुअली शुभारंभ करने के समाचार को –द्वीप समाचार ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बैठक आयोजित करने के समाचार को–अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी की खबर है। सांसद बिष्णु पद ने के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने के समाचार को–द इको ऑफ इंडिया ने सचित्र प्रकाशित किया है।

<><><><><><><>